Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

WRITERS CREW INTERNATIONAL RESEARCH

JOURNAL

भारत में मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली की मांग: एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. कमल पाण्डेय

डैबहैंड असाइनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक

शैक्षिक सलाहकार

दिल्ली

सार

देश के राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो युवाओं को रोजगार कौशल विकसित करके आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाती है और इस प्रकार गरीबी को कम करती है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। इस शोधपत्र में भारत के साथ छह देशों - यूके, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली के घटकों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। शोधपत्र शैक्षिक सुधारों का प्रस्ताव करता है और भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन और बेहतर मूल्य प्रदान करने के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करता है। यह अध्ययन भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में मूल्य की आवश्यकता का संपूर्ण दृष्टिकोण देता है।

मुख्य शब्दः उच्च शिक्षा प्रणाली, मूल्य-आधारित प्रणाली, युवा सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, शैक्षिक सुधार।

ISSN: 3048-5

541Online

परिचय

उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग का प्रतिनिधित्व विश्व भर में 2000 में 100.8 मिलियन तृतीयक छात्रों से 2007 में 152.5 मिलियन तक की वृद्धि द्वारा किया जाता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में दुनिया भर में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है (किर्प, 2003; मारिंगे और गिब्स, 2009)।

यूनेस्को के अनुसार, "उच्च शिक्षा अब एक विलासिता नहीं है; यह राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है"। सभी के लिए शिक्षा (EFA) प्राप्त करने की खोज मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि बच्चे, युवा और वयस्क अपने जीवन को बेहतर बनाने और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायसंगत समाजों के निर्माण में भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। यही कारण है कि EFA प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। चूंकि कई समाज बुनियादी शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है जहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए वास्तविक शिक्षा हो सके।

Writers Crew International Research Journal

गुणवत्ता को इस बात के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि समाज शिक्षा के उद्देश्य को कैसे परिभाषित करता है (EFA ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2005)। गुणवत्ता शिक्षा के मूल्य को बढ़ाती है। इसलिए आजकल शिक्षा के मूल्य को बढ़ाने का बहुत महत्व है। इस पत्र में, भारत में उच्च शिक्षा में मूल्य की माँग को समझाने का प्रयास किया गया। अप्रैल 2000 में डकार, सेनेगल में विश्व शिक्षा मंच में अपनाए गए छह लक्ष्य, स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से गुणवत्ता के आयाम को एकीकृत करते हैं। लक्ष्य हैं प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, युवा और वयस्क शिक्षा, साक्षरता, लिंग और गुणवत्ता। जो देश लक्ष्य 1 से 5 को प्राप्त करने से सबसे दूर हैं, वे लक्ष्य 6 को प्राप्त करने से भी सबसे दूर हैं। कई संकेतक गुणवत्ता के आयामों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय अमीर देशों में सकल घरेलू उत्पाद का उच्च अनुपात दर्शाता है, जहाँ EFA लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, जबकि गरीब देशों में, जहाँ कम संसाधन वाली प्रणालियों के कवरेज को विस्तारित और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। पिछले दशक में कई विकासशील देशों में खर्च में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से पूर्वी एशिया और प्रशांत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में। उप-सहारा अफ्रीका (क्षेत्रीय औसत: 44:1) और दक्षिण और पश्चिम एशिया (40:1) के कई देशों में छात्र/शिक्षक अनुपात

ISSN: 3048-5

541Online

वांछनीय से अधिक बना हुआ है। कई कम आय वाले देशों में, शिक्षक शिक्षण में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं और कई ने पाठ्यक्रम में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण स्कोर के डेटा से पता चलता है कि अधिकांश विकासशील क्षेत्रों में कम उपलब्धि व्यापक है। लक्ष्य 6, विशेष रूप से, देशों को अपने EFA भागीदारों के समर्थन से शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इससे शिक्षा के मूल्य में सुधार होता है। अधिकांश शिक्षा प्रणालियों के केंद्रीय स्तंभों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्र जिम्मेदार नागरिकता के अभ्यास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त करें। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य ऐसे शिक्षित पुरुषों और महिलाओं की एक बड़ी आबादी का निर्माण करना है जो दुनिया को अच्छी तरह से समझ सकें और पर्याप्त स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, बेहतर पर्यावरण और अज्ञानता और अभाव (सीमाओं) को खत्म करने के लिए बदलाव लाने में सक्षम हों, जो विकासशील समाजों का गला

घोंट रहे हैं। इसलिए, नीति में समानता, गुणवत्ता और दक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए उन लोगों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है, जो वंचित हैं और दुख में रहते हैं (राव, 2004)[1]।

अगले कुछ दशकों में, भारत में संभवतः दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा लोग होंगे। भले ही दूसरे देश बूढ़े होने लगें, लेकिन भारत युवाओं का देश बना रहेगा। अगर कुल आबादी में कामकाजी आबादी का अनुपात बढ़ता है, तो इसका असर देश की बचत दर में तेज़ी से दिखाई देगा। और अगर भारत कामकाजी आबादी के लिए उत्पादक रोज़गार के अवसर पा सकता है, तो इससे भारत को सामाजिक और आर्थिक विकास की दौड़ में आगे निकलने का एक बड़ा अवसर मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप विकास दर बढ़ेगी। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देश बढ़ती उम्र की आबादी की समस्या का सामना कर रहे हैं और भारत इस नियम का अपवाद है। इसलिए, यह भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की दौड़ में आगे निकलने का अवसर हो सकता है। भारत के युवा तभी संपत्ति बन सकते हैं, जब उनकी क्षमताओं में निवेश हो। ज्ञान से प्रेरित पीढ़ी[2] एक संपत्ति होगी। अगर इस निवेश से वंचित किया गया, तो यह एक

[1] राव (2004), "सभी के लिए शिक्षा", पृ.: 255

[2] जिसमें ज्ञान का उत्पादन और उसका दोहन धन सृजन में प्रमुख भूमिका निभाने लगा है।

सामाजिक और आर्थिक दायित्व बन जाएगा। इसलिए, आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान के आधार के निर्माण में निवेश होना चाहिए (मनमोहन, 2005)[3]. इसलिए मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में आज 250 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, और कई अनुसंधान और विकास इकाइयाँ, और व्यावसायिक कॉलेज और संस्थान हैं। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास संस्थानों की दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखला है। औसतन, हर साल 350,000 से अधिक इंजीनियर और 5,000 पीएचडी विद्वान भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से स्नातक होते हैं। योग्य, अंग्रेजी बोलने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति के इतने विशाल पूल के साथ, भारत में अनुसंधान का एक बड़ा आधार और विकास गतिविधि का केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत को घरेलू स्तर पर अनुसंधान और विकास गतिविधि में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए और आवश्यक कानूनी और भौतिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना चाहिए जो अनुसंधान और विकास गतिविधि में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके (मनमोहन, 2005)। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की सिफारिशें भारत के

---

[3] डॉ. मनमोहन सिंह ने ज्ञान आयोग के शुभारंभ पर टिप्पणी की है

ज्ञान के विशाल भंडार का दोहन करने, राष्ट्रीय प्रतिभा को संगठित करने और जबरदस्त संभावनाओं तक पहुँच के साथ एक सशक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई हैं। 25 वर्ष से कम आयु के 550 मिलियन लोगों के साथ, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश सबसे बड़ी संपत्ति है। शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में सुधारों की सिफारिश करके, एनकेसी का उद्देश्य इस मानव पूंजी का दोहन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसमें देश में विकास की दिशा बदलने की क्षमता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी सिफारिशें सुझाई गई हैं, क्योंकि इस क्षमता का पर्याप्त रूप से दोहन करने के लिए, बौद्धिक पूंजी में निवेश करके, आबादी के कौशल सेट को विकसित करके, अनुसंधान को मजबूत करके, नवाचार और उद्यमशीलता[4] को प्रोत्साहित करके और ई-गवर्नेंस की प्रभावी प्रणाली बनाकर सही विकास प्रतिमान बनाया जाना चाहिए (सैम, 2009)[5]।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मूल्य-आधारित उच्च शिक्षा के निर्माण में सहायक कारकों का पता लगाना।

[4] उद्यमिता एक उद्यमी होने का कार्य है। उद्यमी नवाचारों को आर्थिक वस्तुओं में बदलने के प्रयास में नवाचारों, वित्त और व्यावसायिक कौशल सहित संसाधनों को इकट्ठा करते हैं।

[5] सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा, सैम (2009), "ज्ञान समाज की ओर", एनकेसी जन समाचार पत्र।

Writers Crew International Research Journal

2. दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों से लिए गए छह अलग-अलग देशों के साथ भारत की उच्च शिक्षा की तुलना करना। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका।

3. भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना।

पद्धति

इस शोध पत्र में, शोध विभिन्न शोध रिपोर्टों, पत्रिकाओं और शोध पत्रों से लिए गए द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित था। शोध छह देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की मूल्य आधारित उच्च शिक्षा के घटकों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित था।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली

प्राचीन काल से ही भारत में उच्च शिक्षा की एक मजबूत परंपरा रही है। यह बौद्ध मठों जैसे शिक्षण केंद्रों से स्पष्ट है जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद थे और नालंदा जो तीसरी शताब्दी ईस्वी में मौजूद था (पेर्किन, 2006)। इनमें से कुछ केंद्र बहुत बड़े थे, जिनमें कई संकाय थे। देश में आक्रमणों और अव्यवस्था ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया है (अंग्रेजों ने

वैज्ञानिक जांच पर जोर देते हुए पश्चिमी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को भारत में लाया। पहला कॉलेज 1918 में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था, जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रदान की। 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और 27 कॉलेज उनसे संबद्ध थे। 1947 में, भारत में 19 विश्वविद्यालय पहले से ही अस्तित्व में थे (सीएबीई, 2005), जबकि स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा प्रणाली तेजी से बढ़ी। 1980 में, देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 132 और कॉलेजों की संख्या 4738 थी, जिसमें योग्य आयु वर्ग के 5% लोग उच्च शिक्षा में नामांकित थे। छात्र नामांकन, जो 1987 और 1993 के बीच बढ़ा, 7% था, लेकिन घटकर 1993 में 19% हो गया। 5.5% की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा संस्थानों के सदस्यों की संख्या 1947 से 1948 में 516 से बढ़कर 2005 से 2006 में 17,973 हो गई (भारत सरकार, 2007)।

तालिका 1. उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की संख्या, 2005-06।

Institution	Enrolment (in thousands)	Teachers (in thousands)	Student:Teacher ratio
University Departments and University Colleges	1427	79	18
Affiliated Colleges	9601	409	23
Total	11028	488	22

स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2005-06।

भारत में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार इसकी गुणवत्ता की कीमत पर हुआ है, क्योंकि गुणवत्ता संस्थानों के साथ बदलती रहती है। संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली तीन एजेंसियाँ हैं। इन एजेंसियों का मूल्यांकन देश में बाहरी गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से किया जाता है। ये हैं उच्च शिक्षा के संस्थानों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)[6], इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA), और प्रत्यायन[7] जो छात्रों को धोखाधड़ी और दुरुपयोग से नहीं बचाता है। भारत में जन जागरूकता बहुत कम है। भारत में, देश में उच्च शिक्षा पर सांख्यिकीय जानकारी के संग्रह और संकलन की कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन

[6] मूल्यांकन आउटपुट की गुणवत्ता का एक विचार देता है। मूल्यांकन के विशिष्ट परिणाम में एक बहु-बिंदु ग्रेड होता है - संख्यात्मक या शाब्दिक या वर्णनात्मक।

[7] प्रत्यायन एक मूल्यांकन है कि क्या कोई संस्थान (या कार्यक्रम) एक निश्चित स्थिति के लिए योग्य है।

प्रत्यायन बाइनरी स्केल में परिणाम प्रदान करता है - हाँ/नहीं या
मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त।

Writers Crew International Research Journal

विकास मंत्रालय ने यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को सौंपी। हालाँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ऐसा करने में विफल रहा है (अग्रवाल, 2006)। भारत की वार्षिक विकास दर 9% से अधिक है। विकास दर को बनाए रखने के लिए भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि की आवश्यकता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शिक्षा के लिए वार्षिक योजना (2007 से 2012) की स्थापना की घोषणा की है, जिसकी योजना राशि 2500 अरब रुपये है, जो पिछली योजना से चार गुना अधिक है। वर्ष 2006 में 11वीं पांच संस्थाओं में 355 विश्वविद्यालय और 18,064 कॉलेज हैं, हालांकि 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 216 राज्य विश्वविद्यालय, 101 डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य विधान के माध्यम से स्थापित 5 संस्थान और 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान मौजूद हैं। वर्ष 2005 से 2006 के बीच भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों का नामांकन लगभग 110 लाख होने का अनुमान है। चित्र 2 दर्शाता है कि भारत में उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन की वृद्धि असमान और धीमी रही है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2001 से 2002 में नामांकन में 6.7% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2005 से 2006 में इसमें 5.2% की वृद्धि हुई। तालिका 1 में दर्शाए अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की कुल संख्या 4.88 लाख है। कुल शिक्षण संकाय में से 84% संबद्ध महाविद्यालयों में

कार्यरत थे और केवल 16% विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कार्यरत थे। छात्र-शिक्षक अनुपात विश्वविद्यालय विभागों और महाविद्यालयों में 18 और संबद्ध महाविद्यालयों में 23 है।

चित्र 1 भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है। यह वर्ष 1950 से 2006 तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में उच्च वृद्धि दर्शाता है।

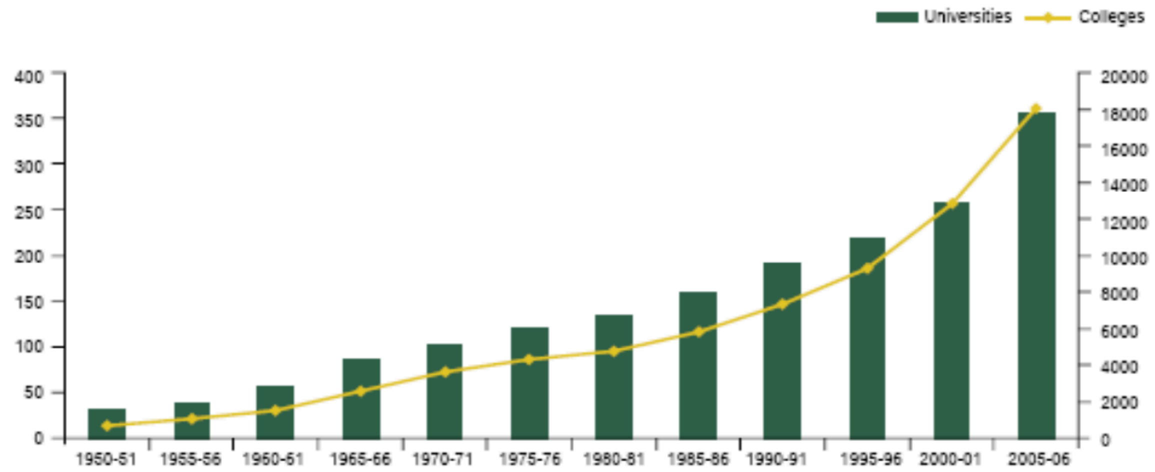

चित्र 1. उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास। स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

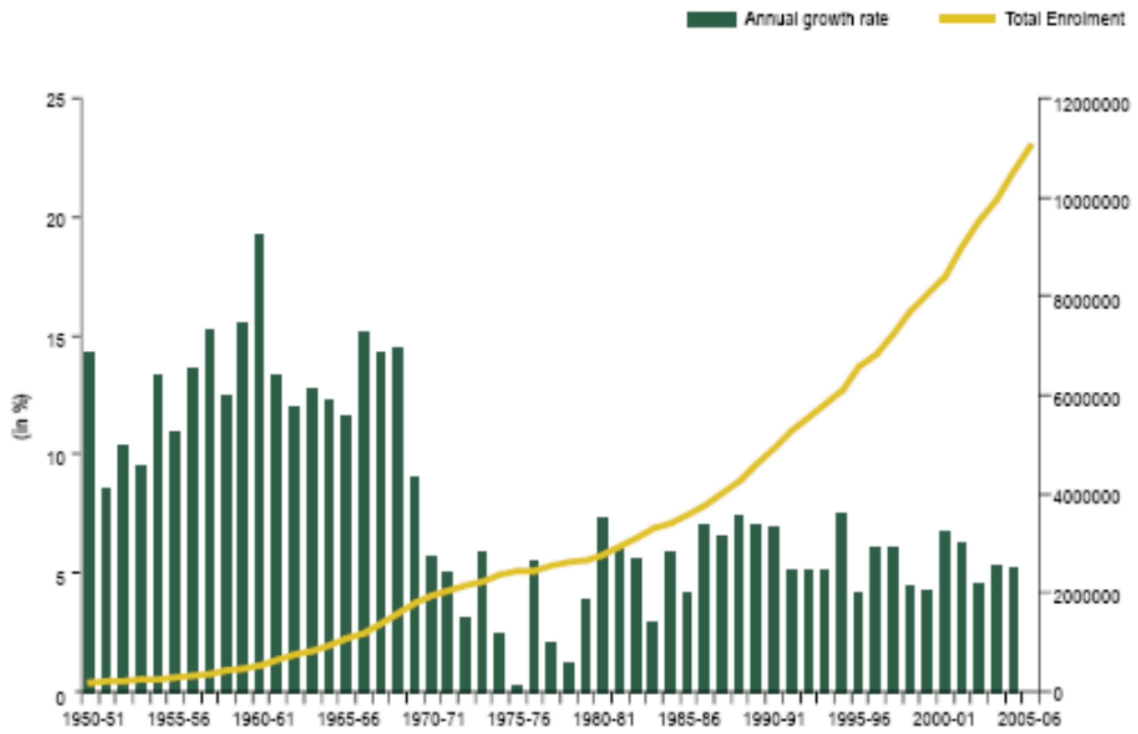

चित्र 2. भारत में उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन की वृद्धि (1950-51 से 2005-06)। स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

मूल्य आधारित भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता किसी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मानव पूंजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। भारत में, शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। इसलिए, साक्षरता के स्तर को उच्च बनाने में राज्य की भूमिका

बहुत महत्वपूर्ण है। गलत प्रकार के राज्य हस्तक्षेप या बहुत कम राज्य हस्तक्षेप के कारण निजी क्षेत्र की भूमिका भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.37%12 उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है और हाल के वर्षों में इसमें भी कमी आ रही है। इसलिए, विकसित देशों में शिक्षा में ”बाजार को छोड़कर व्यवस्था” के बजाय ”बाजार पूरक व्यवस्था” हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता का स्तर व्यापक होगा (भारत सरकार, 2007)।

Year	Higher Education
2001-02	8.07
2002-03	8.97
2003-04	9.21
2004-05	9.97

तालिका 2. 18-24 वर्ष के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (प्रतिशत में)।

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

Details	Number (%)
Total umber of colleges	17,625
Number of colleges under UGC purview	14,000
Number of colleges recognized under Section 2(f) of UGC Act	5,589 (40)
Number of colleges recognized under Section 12(B) of UGC Act	5,273 (38)
Number of colleges actually funded by the UGC	4,870 (35)
Number of colleges accredited by the NAAC	2,780 (20)
Number of colleges accredited by the NAAC and scoring above 60 per cent	2,506 (17.9)

तालिका 3. भारत में उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में वर्तमान गुणवत्ता स्थिति (2005)।

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

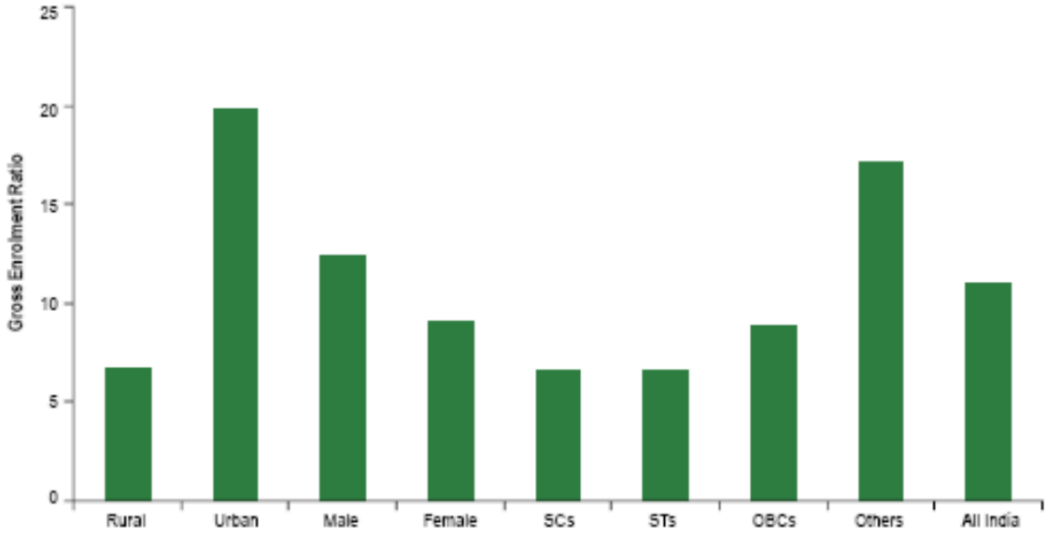

चित्र 3. उच्च शिक्षा में नामांकन में असमानताएँ (2004-05)।

स्रोत: यूजीसी।

ISSN: 3048-5

541Online

भारत सरकार ने एनपीई[8] की सिफारिशों के बाद पांच-स्तरीय रणनीति अपनाई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में सुधार।

2. बेहतर पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रावधान।

3. बाल-केंद्रित शिक्षाशास्त्र की शुरूआत के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार।

4. शिक्षक क्षमता निर्माण पर ध्यान।

5. शिक्षार्थी उपलब्धि स्तरों के विनिर्देशन और माप पर अधिक ध्यान।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार किसी निश्चित समय-सीमा में टर्न-की आधार पर नहीं किया जा सकता। इसलिए रणनीति में उल्लिखित सभी मोर्चों पर आगे बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की गई हैं। साथ ही, सभी ईएफए परियोजनाओं में गुणवत्ता सुधार घटक को उच्च

[8] शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति

प्राथमिकता दी गई है (राव, 2004)। वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली ढांचे में कुछ मुद्दे हैं जो इस प्रकार हैं।

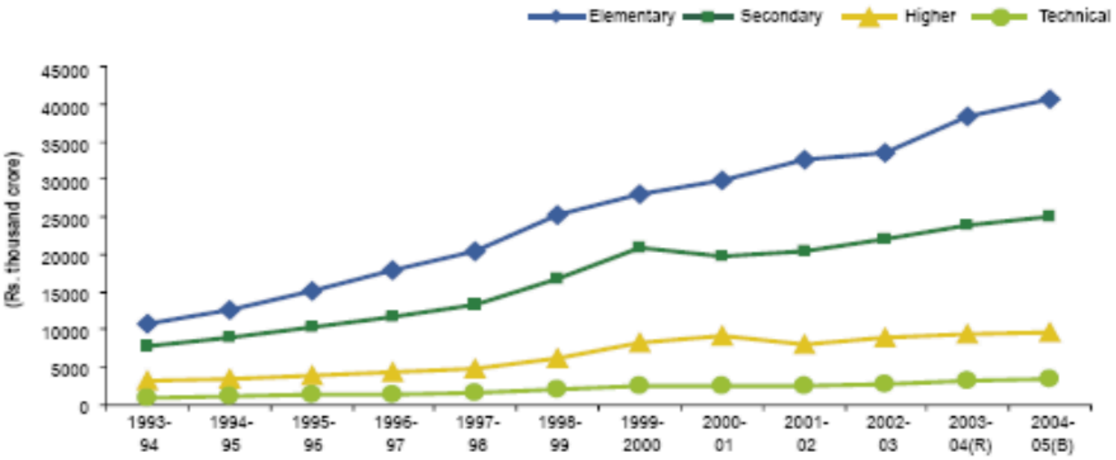

चित्र 4. राज्य और केंद्र के शिक्षा विभागों के लिए क्षेत्रवार योजना और गैर-योजना बजटीय व्यय (राजस्व लेखा)। स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

विस्तार

उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन लगभग 11 मिलियन है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा में नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में यह पर्याप्त नहीं है (चित्र 2)। उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित 18 से 24 आयु वर्ग का प्रतिशत) लगभग 8 से 10% है, जबकि कई अन्य विकासशील देशों के लिए यह 25% है

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

Writers Crew International Research Journal

541Online

(तालिका 2)। भारत में उच्च शिक्षा परिदृश्य की जांच करने वाली विभिन्न समितियों[9] ने जीईआर में कम से कम 20% की वृद्धि की सिफारिश की है। यदि भारत को जल्द ही लक्ष्य हासिल करना है, तो इसका मतलब है कि अगले 5 से 7 वर्षों के भीतर उच्च शिक्षा प्रणाली के पैमाने और आकार को दोगुना से भी अधिक करना होगा। तालिका 2 प्रतिशत में 18 से 24 वर्ष के लिए जीईआर दिखाती है। तालिका 3 के अनुसार, 2001 से 2005 तक जी.ई.आर. का प्रतिशत हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2002 से 2003 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 0.90 थी, जो 2001 से 2005 के दौरान अधिकतम वृद्धि दर्शाती है। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम वृद्धि 2003 से 2004 में 0.24 थी।

पहुँच

उच्च असमानताओं के साथ, समावेशी शिक्षा एक मायावी लक्ष्य बनी हुई है। नामांकन में अंतर-जाति, पुरुष-महिला और क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सकल नामांकन अनुपात लगभग 20% था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह केवल 6% था। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों (एसटी),

[9] उच्च शिक्षा के वित्तपोषण पर समिति, CABE ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकाला है

ISSN: 3048-5

541Online

अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 6.57, 6.52 और 8.77 था, और यह भारत में सभी जीईआर से बहुत कम था (चित्र 3)।

विनियमन

वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में विनियामक संरचनाएँ बोझिल हैं। वर्तमान में, केवल कानून के माध्यम से प्रवेश एक कठिन बाधा है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद के विधानमंडल के अधिनियम की आवश्यकता होती है। नए संस्थानों के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय का मार्ग बहुत कठिन है। इसका परिणाम मौजूदा विश्वविद्यालयों के औसत आकार में लगातार वृद्धि और उनकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट है। अधिकांश कॉलेज यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।[10]

यह उच्च शिक्षा में शिक्षण और परीक्षा के मानक को बनाए रखने के संबंध में यूजीसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही, स्नातक कॉलेजों के लिए संबद्ध कॉलेजों की वर्तमान प्रणाली

[10] अनुभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12बी।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

पर्याप्त नहीं है। ये बड़े बोझिल विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, जिससे दी जा रही शिक्षा के मानक की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में, स्नातक नामांकन का लगभग ९0% और स्नातकोत्तर नामांकन का 67% संबद्ध कॉलेजों में है। बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान हैं जो तकनीकी रूप से यूजीसी के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी जाती क्योंकि वे न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में रैंकिंग

उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित रिपोर्ट पिछले 30 वर्षों से विश्व आर्थिक मंच ने दुनिया भर के देशों की उत्पादक क्षमता का विस्तृत आकलन करके इस प्रक्रिया में एक सहायक भूमिका निभाई है। 'रिपोर्ट' आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों की समझ को बढ़ाने और यह समझाने में योगदान देती है कि कुछ देश अपनी संबंधित आबादी के लिए आय के स्तर और अवसरों को बढ़ाने में दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों हैं; इसलिए, यह नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के नेताओं को बेहतर आर्थिक नीतियों और संस्थागत सुधारों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। 'रिपोर्ट' में अध्ययन में शामिल प्रत्येक

अर्थव्यवस्था के लिए एक विस्तृत प्रोफ़ाइल और साथ ही 100 से अधिक संकेतकों को कवर करने वाली वैश्विक रैंकिंग के साथ डेटा तालिकाओं का एक व्यापक खंड शामिल है। जीसीआई कई अलग-अलग घटकों का भारित औसत प्रदान करके इस खुले आयाम को पकड़ता है, जिनमें से प्रत्येक प्रतिस्पर्धात्मकता की जटिल अवधारणा के एक पहलू को दर्शाता है। वैश्विक आर्थिक मंच इन घटकों को 'प्रतिस्पर्धा के 12 स्तंभों' में समूहित करता है:

1. संस्थान।

2. बुनियादी ढांचा।

3. स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा।

4. व्यापक आर्थिक स्थिरता।

5. उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण।

6. माल बाजार दक्षता।

7. श्रम बाजार दक्षता।

8. वित्तीय बाजार परिष्कार।

9. तकनीकी तत्परता।

Writers Crew International Research Journal

10. बाजार का आकार।

11. व्यावसायिक परिष्कार।

12. नवाचार

सुझाव

(क) भारत को उच्च शिक्षा प्रणाली के मूल्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में सुधार करना होगा, इसके लिए समितियों या संगठनों का गठन करना होगा ताकि वे इन कारकों पर नज़र रख सकें और उनमें सुधार कर सकें। इस प्रकार, इन समितियों और संगठनों के सुझावों को लागू किया जाना चाहिए।

(ख) भारत को शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे।

(ग) सरकार स्नातक तक सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में भी काम कर सकती है।

(घ) सरकार को कार्यक्रमों या अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर आने वाले मोबाइल छात्रों की संख्या में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

निष्कर्ष

सभी के लिए शिक्षा गुणवत्ता और इसलिए मूल्य में सुधार किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। दुनिया के कई हिस्सों में, स्कूल से स्नातक होने वाले छात्रों और उनमें से उन लोगों की संख्या के बीच एक बड़ा अंतर बना हुआ है जो संज्ञानात्मक कौशल के न्यूनतम सेट में महारत हासिल करते हैं। शुद्ध नामांकन को 100% की ओर ले जाने के उद्देश्य से किसी भी नीति को सभ्य सीखने की स्थिति और अवसरों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन देशों से सबक लिया जा सकता है जिन्होंने इस दोहरी चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया है। बेहतर शिक्षा उच्च आजीवन आय और अधिक मजबूत राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देती है और व्यक्तियों को अन्य मामलों में मदद करती है जो उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण से पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति का शिक्षा परिणामों के स्तर पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में गुणवत्ता को परिभाषित करने के अधिकांश प्रयासों की विशेषता दो सिद्धांत हैं: पहला सभी शिक्षा प्रणालियों के प्रमुख स्पष्ट उद्देश्य के रूप में शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान करता है। तदनुसार, जिस सफलता के साथ प्रणालियाँ इसे प्राप्त करती हैं, वह उनकी गुणवत्ता का एक संकेतक है। दूसरा, जिम्मेदार

Writers Crew International Research Journal

नागरिकता के मूल्यों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने और रचनात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देता है। गुणवत्ता में सुधार और न्यायसंगत तरीके से पहुँच का विस्तार करने की दोहरी चुनौती के लिए निरंतर निवेश के स्तर की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में देशों की पहुँच से परे है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करना और देशों के बीच तुलना करना अधिक कठिन है। कम आय वाले देशों में, गुणवत्ता और इसलिए शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव अधिक पाठ्यपुस्तकों के प्रावधान के लिए खर्च बढ़ाने, कक्षा के आकार को कम करने और शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक उपलब्धि पर शिक्षक शिक्षा और बुनियादी ढाँचा सुविधाओं में सुधार करके होता है। अमीर देशों में, मानक कम आय वाले देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं। गुणवत्ता में सुधार बहुत मामूली लागत पर बढ़ाया जा सकता है और सबसे गरीब देशों में भी पहुँच के भीतर है। शिक्षा की गुणवत्ता सभी के लिए शिक्षा के केंद्र में है। यह निर्धारित करता है कि छात्र कितना और कितनी अच्छी तरह सीखते हैं, और उनकी शिक्षा किस हद तक व्यक्तिगत, सामाजिक और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करती है। इसलिए, यह शोध पत्र गुणवत्ता को समझने, निगरानी करने और सुधारने के लिए एक मानचित्र प्रस्तुत करता है। शिक्षा की गुणवत्ता, चाहे वह कम हो या अधिक, उसके उद्देश्यों की पूर्ति की सीमा से आंकी जाती है।

सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसी नीतियाँ मौजूद हैं जो ज़रूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा संसाधन विवश देशों की पहुँच से परे हों। वे सीखने वाले पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं और वे शिक्षण और सीखने की गतिशीलता पर ज़ोर देते हैं, जो स्कूलों और शिक्षकों को प्रभावी बनाने वाले शोध के बढ़ते निकाय द्वारा समर्थित है। शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर सरकार की विभाजित मशीनरी द्वारा छिपे या अनदेखा किए जाते हैं। सफल गुणात्मक सुधारों के लिए सरकार को एक मजबूत अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। हालाँकि बाहरी सहायता संसाधन स्तरों को बढ़ा सकती है और शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन में मदद कर सकती है, लेकिन यह शैक्षिक सुधार के लिए एक सामाजिक परियोजना की अनुपस्थिति की भरपाई नहीं कर सकती है। तदनुसार, घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया अंततः सफल सुधार की गारंटी है। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। सूचनाप्रद नीति-निर्माण में विशेषीकृत संस्थाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। एन.के.सी. ऐसे तरीके सुझाता है जिससे केंद्र और राज्य सरकारें नियमों और विनियमों तथा ज्ञान संस्थानों से संबंधित नीति-निर्माण संस्थाओं की

क्षमता में सुधार कर सकती हैं। ज्ञान आयोग के पास शोध और शिक्षण में उत्कृष्टता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्ताव हैं, विशेष रूप से गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में। ऐसे में भारत बाकी दुनिया से पीछे नहीं रह सकता। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता उत्कृष्टता के लिए और भारत को बौद्धिक प्रयासों का केंद्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह समय शिक्षा, शोध और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्था निर्माण और उत्कृष्टता की दूसरी लहर पैदा करने का है ताकि भारत 21वीं सदी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। ज्ञान आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के 'ज्ञान आधार' को बढ़ावा देने और इसकी विशाल अव्यक्त क्षमता का दोहन करने के लिए रचनात्मक विचारों के साथ आगे आया है। एनकेसी को इसका लाभ उठाकर भारत को वास्तव में विश्व का 'ज्ञान इंजन' बनाना चाहिए (मनमोहन, 2005)24. यदि इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में सक्षम होगा और युवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाएंगे। इसके अलावा, शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण समुदायों, शहरी मलिन बस्तियों, आदिवासी समूहों और अन्य आर्थिक और सामाजिक रूप से

ISSN: 3048-5

541Online

वंचित समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जबरदस्त अवसरों में तब्दील हो जाएगा और भारत को एक अधिक समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ने में मदद करेगा।

संदर्भ सूची

- अग्रवाल (2006)। "भारत में उच्च शिक्षा- परिवर्तन की आवश्यकता", कार्य पत्र संख्या: 180, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER), भारत।
- अग्रवाल (2007)। "भारत में उच्च शिक्षा सेवाएँ और व्यापार उदारीकरण", रूपा चंदा (संपादक), सेवाओं में व्यापार और भारत की संभावनाएँ और रणनीतियाँ।
- CABE समिति (2005)। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) समिति की रिपोर्ट। भारत सरकार। जून 2005।
- EFA वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (2005)। यूनेस्को।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (2009-2010)।

- **विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट (2008), यूनेस्को।**
- **कपूर, मेहता (2004)। भारतीय उच्च शिक्षा सुधार: आधे-अधूरे समाजवाद से आधे-अधूरे पूंजीवाद तक। सीआईडी वर्किंग पेपर नं. 108. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट।**
- **किर्प डी (2003)। शेक्सपियर, आइंस्टीन और बटम लाइन: उच्च शिक्षा का विपणन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। कैम्ब्रिज। एमए।**
- **मारिंग एफ, गिब्स पी (2009)। उच्च शिक्षा का विपणन: सिद्धांत और व्यवहार। ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस। मैकग्रॉ-हिल एजुकेशन। इंग्लैंड।**
- **न्यू नॉलेज कमीशन (2008)। दिसंबर न्यूज़लेटर। न्यू नॉलेज कमीशन (2009)। ”रिपोर्ट टू द नेशन, 2006-2009”, भारत सरकार।**
- **न्यू नॉलेज कमीशन (2009)। जनवरी न्यूज़लेटर। पिंटो एम (1984)। संघवाद और उच्च शिक्षा: भारत का अनुभव।**
- **बॉम्बे, भारत, ओरिएंट लॉन्गमैन। राव (2004)। ”सभी के लिए शिक्षा”। सोनाली प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ: 243-244, 255।**

ISSN: 3048-5

541Online

- व्यापार नीति प्रभाग (2006)। "शिक्षा सेवाओं में व्यापार, भारत में उच्च शिक्षा और GATS पर परामर्श पत्र: एक अवसर", वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, भारत। यूजीसी (2006-2007)। यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार।